वन ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का खाका खींचा

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राज्य को हर साल पांच लाख करोड़ रुपये की निवेश की जरूरत होगी। अभी 3,29,127 करोड़ रुपये का निवेश होता है। ऐसे में हर साल 1,70,873 करोड़ रुपये के निवेश की और जरूरत होगी। यही नहीं सरकार को इन पांच लाख करोड़ के निवेश में सबसे 12.6 प्रतिशत बजटीय प्रावधान जल जंगल, जमीन, जल वायु क्षेत्र में करना होगा।

यह तथ्य सोमवार को जारी अध्ययन रिपोर्ट में दिए गए हैं। माइक्रो फाइनेन्स एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश (उपमा) द्वारा सम्मेलन में बैंकिंग व वित्त विशेषज्ञों ने इस लक्ष्य को पाने के लिए कई तरह के सुझाव दिए।

■ माइक्रो फाइनेन्स रोजगार में सहायक बनकर महिलाओं को स्वावलंबी बना रहा है : असीम अरुण

रिपोर्ट में कहा गया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, व कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण युक्त खनन व वैकल्पिक ऊर्जा, आवासीय व इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला स्वयं सहायता समूह, किसान समूह, युवा सहकारी उद्यमिता, भूमिहीनों को पेंशन, किसानों को ऋण उपलब्धता- इन सभी सेक्टर में 6.3 प्रतिशत का बजटीय प्रावधान होना चाहिए। क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिए पूर्वांचल व बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

मुख्य अतिथि के तौर पर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं द्वारा अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दिए जा रहे सहयोग और उनके योगदान द्वारा महिलाओं के जीवन स्तर मे हो रहे सुधार पर प्रसन्नता जताई।